बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 107 ● नई दिल्ली ● वीरवार 05 फरवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

संसद में हंगामा : विपक्ष पर बरसे स्पीकर ओम बिरला, लोकसभा में सांसदों के साथ नारेबाजी पर मर्यादा का पाठ पढ़ाया

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र में पक्ष-विपक्ष के बीच जोरदार तकरार देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां राहुल गांधी अपने चीन सीमा विवाद वाले मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं, वहीं सरकार की तरफ से इसका जवाब दिया जा रहा है। इसी बीच एक दिन पहले भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर भी विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। एक दिन पहले भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और आज वे लोकसभा में भी इस मुद्दे पर बोलने के लिए खड़े हुए। उनके भाषण के दौरान विपक्षी सांसदों ने टेबल पीटकर और हंगामा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विपक्ष ने राहुल गांधी को बोलने देने के लिए नारेबाजी की और खेल में भी आ गए।

मनजिंदर सिंह सिरसा का दावा, बजट में दिल्लीवालों के लिए खुशियों की सौगात, गरीबों के लिए योजनाएं

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट को देश और दिल्ली के लिए बेहद अहम बताया है. उन्होंने कहा कि यह बजट ऐसे समय में आया है, जब पूरी दुनिया आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही है. ऐसे माहौल में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में यह बजट एक मजबूत आधार तैयार करता है. मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं, गरीबों और छोटे व्यापारियों का विशेष ध्यान रखा गया है. सरकार का लक्ष्य किसानों की आमदनी को दोगुना करना है. इसके लिए खेती में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा और किसानों को एआई आधारित सिस्टम की सुविधा मिलेगी. उन्होंने बताया कि देश के करीब 10 करोड़ छोटे किसानों के लिए 63,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ मिलेगा.

महिला सशक्तिकरण पर फोकस

महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर मंत्री ने कहा कि यह बजट पूरी तरह महिला-केंद्रित है. देशभर में गर्ल्स हॉस्टल के लिए 10,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं और महिला कल्याण से जुड़े बजट में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. इसके साथ ही लखपति दीदी 2.0 योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत बहन-बेटियों को 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा. महिलाओं के लिए नए स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी.

इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप को बढ़ावा

इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए गए हैं. देश में 7 हाई-स्पीड रेल

कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनमें दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट भी शामिल है. छोटे व्यापारियों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का ग्रोथ फंड लाया गया है. स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग 2.0 के तहत 900 करोड़ रुपये का फंड दिया गया है, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. बायो-फार्मा सेक्टर के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

गरीबों के लिए आवास और रोजगार

गरीबों के लिए इस बजट को संजीवनी बताते हुए मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 54,917 करोड़ रुपये गरीबों के घर बनाने के लिए दिए जाएंगे. रोजगार गारंटी के तहत 125 दिनों का काम सुनिश्चित किया जाएगा, जिसके लिए 95,692 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है.

शिक्षा के क्षेत्र में 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित होंगी और कंटेंट क्रिएशन के लिए लैब बनाई जाएंगी, जिससे करीब 20 लाख प्रोफेशनल्स को मदद मिलेगी. स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3 बड़े आयुर्वेदिक संस्थान खोले जाएंगे.

दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान

दिल्ली को लेकर सिरसा ने बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत 82 योजनाओं में 13,000 करोड़ रुपये से यादा की राशि मिलेगी. दिल्ली पुलिस के लिए 12,500 करोड़ और दिल्ली के केंद्रीय अस्पतालों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जिससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी. उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार मार्केट बॉरोइंग के तहत 21,000 करोड़ रुपये तक का कर्ज ले सकेगी, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी. साथ ही दिल्ली सरकार ने होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा पूरा किया है. होली पर महिलाओं को जल्द मुफ्त सिलेंडर मिलेगा. जिन लोगों को राशन मिलता है, ऐसे करीब 17.50 लाख लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से पैसा दिया जाएगा.

विपक्ष पर साधा निशाना

मनजिंदर सिंह सिरसा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग 11 साल तक कोई काम नहीं कर पाए, वे आज विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह बजट आम आदमी, गरीब, किसान और महिलाओं के लिए राहत लेकर आया है और देश को विकास की नई दिशा देगा.

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को संसद भवन में मिला कमरा,अटल और आडवाणी का भी रह चुका ठिकाना

नई दिल्ली । भारतयी जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन को संसद भवन में अपना कमरा मिल गया है. ये वही कमरा है जिसमें एक समय में अटल बिहारी वाजपेयी और एलके आडवाणी जैसे नेता भी बैठते थे. नितिन नवीन को पुराने संसद भवन में बीजेपी कार्यालय के पास कमरा नंबर चार दिया गया है. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को लुटियन दिल्ली में सरकारी बंगला मिलने के बाद अब संसद भवन परिसर में भी कमरा मिल गया है. पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाता है. सभी राष्ट्रीय दलों के कार्यालय इसी भवन में हैं. कुछ राज्य मंत्रियों के कार्यालय भी इसी इमारत में हैं. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को जो चार नंबर कमरा मिला है. इस कमरे की कहानी अपने आप में बेहद दिलचस्प है. इस कमरे से ऐतिहासिक रूप से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व उपप्रधानमंत्री लाल कृष्ण

आडवाणी का जुड़ाव रहा है. ग्राउंड फ्लोर पर स्थित यह कमरा नंबर 4 भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है.यह कमरा 2004 के लोकसभा चुनावों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को एनडीए अध्यक्ष के रूप में आवंटित किया गया था. इसे जनता दल (यूनाइटेड) ने एनडीए के उपयोग के लिए उपलब्ध कराया था. यह भाजपा संसदीय दल के कार्यालय के ठीक बगल में है.हालांकि, वाजपेयी ने इस कमरे का कभी उपयोग नहीं किया. 2004 में एनडीए की हार के बाद 80 वर्षीय वाजपेयी स्वास्थ्य खराब होने के कारण सक्रिय राजनीति से दूर हो चुके थे.वे कभी इस कमरे में नहीं आए लेकिन कमरे के बाहर उनकी नेमप्लेट लगी रही. 2018 में उनके निधन के बाद भी नेमप्लेट बरकरार रही. यह कमरा 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी को एनडीए के अध्यक्ष के रूप में आवंटित किया गया. लंबे समय तक आडवाणी की नेमप्लेट वाजपेयी के साथ ही लगी रही. वे 2019 तक इसका नियमित उपयोग करते रहे. 2019 के बाद यह कमरा खाली रहा. फिर 2021 में वाजपेयी और आडवाणी के नेमप्लेट हटा दिए गए और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को यह कमरा आवंटित किया गया. जेपी नड्डा पहले तत्कालीन राज्यसभा नेता थावरचंद गहलोत के साथ कमरा शेयर करते थे। बाद में जगह की कमी को देखते हुए उन्हें कमरा नंबर चार दिया गया.अब नितिन नवीन इस कमरे में संसद सत्र के दौरान बैठेंगे. इस तरह संविधान सदन का यह कमरा बीजेपी में नेतृत्व और पीढ़ी के परिवर्तन का प्रतीक बन गया है.

ओल्ड राजेंद्र नगर हादसा : सीबीआई बोली- आगे जांच की जरूरत नहीं, पीड़ित पिता ने उठाए सवाल

नई दिल्ली । दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में जुलाई 2024 में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से सिविल सेवा के अभ्यर्थियों की मौत के मामले में सीबीआई ने साफ कहा है कि अब किसी और जांच की जरूरत नहीं है. सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करते हुए बताया कि मामले से जुड़ा हर सबूत जुटाया जा चुका है और सभी पहलुओं से जांच पूरी कर ली गई है. यह जवाब मृतक नेविन डाल्विन के पिता डाल्विन सुरेश की ओर से दायर उस याचिका पर दिया गया है, जिसमें आगे जांच की मांग की गई थी. राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील अभिजीत आनंद ने आरोप लगाया कि सीबीआई ने निष्पक्ष और पूरी जांच नहीं की और कई अहम पहलुओं को नजरअंदाज किया गया. उनका कहना है कि जांच अधिकारी ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के बावजूद सभी कोणों से मामले की पड़ताल नहीं की. सीबीआई ने अदालत को बताया कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष, कानून के मुताबिक और दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप की गई है. एजेंसी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी आरोपी, एमसीडी या फायर सर्विस के अधिकारियों के साथ कोई मिलीभगत नहीं की गई है. राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई के मुताबिक जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में जिन विभागीय लापरवाहियों की बात है, वे जरूरी नहीं कि आपराधिक लापरवाही साबित हों. आपराधिक जिम्मेदारी के हर पहलू की जांच की जा चुकी है. सीबीआई ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड, एमसीडी के करोल बाग जोन के डिप्टी कमिश्नर और संबंधित इंजीनियरों की भूमिका की भी गहन जांच की गई है. जांच में यह भी सामने आया कि ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में पहले से जलभराव की समस्या रहती थी और कोचिंग सेंटर बेसमेंट में चलाया जा रहा था, जिसे चार्जशीट में शामिल किया गया है. हालांकि कोर्ट में पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इमारत की ऊंचाई 15 मीटर से यादा थी और कुछ बड़े अधिकारियों को बचाया जा रहा है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई बुधवार को तय की है. दरअसल 2 अगस्त 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपते हुए पूरी और व्यापक जांच के निर्देश दिए थे और शुरुआती पुलिस जांच पर कड़ी टिप्पणी भी की थी. मामला अभी भी विवादित बना हुआ है और पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं.

कोका-कोला की दो बोतलें फटने से घर को हुआ नुकसान, अब 13 साल बाद देना होगा मुआवजा; चार सप्ताह की मोहलत

नई दिल्ली । दिल्ली के एक परिवार को वर्ष 2012 में कोका-कोला की दो बोतलें फटने से बड़ा नुकसान हुआ था। इस मामले में उपभोक्ता अदालत ने कंपनी पर सख्ती दिखाते हुए 1 लाख रुपये मुआवजा और 50 हजार रुपये मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया है। अध्यक्ष पूनम चौधरी, सदस्य बारीक अहमद और शेखर चंद्र की अदालत ने सुनवाई के बाद पाया कि कंपनियां लापरवाह थीं और उनकी हरकत अनुचित व्यापार व्यवहार थी। अदालत ने कहा कि बोतलें घर में रखी थीं, तो फटने का दोष कंपनी का है। रकम चार हफ्ते में नहीं दी तो ब्याज भी लगेगा। तरुण राजपाल नाम के एक बायोटेक्नोलॉजी छात्र ने 2012 में रिलायंस फ्रेश से छह 2 लीटर की कोका-कोला बोतलें खरीदी थीं। 11 अगस्त 2012 को शाम को किचन में एक बोतल अचानक फट गई, जैसे कोई छोटा बम हो। इससे फर्श और दीवारें गंदी हो गईं और कुछ सामान गर्म तेल में गिर गया। तरुण की 68 साल की मां, जो हाई ब्लड प्रेशर की मरीज हैं। वह इस डर से बीमार पड़ गईं और डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। माइक्रोवेव, वॉटर प्यूरीफायर, मिक्सर और मोबाइल फोन भी खराब हो गए। पांच दिन बाद दूसरी बोतल फटी, जिसका धमका और जोरदार था। इससे तरुण के दिल की बीमारी के मरीज 75 साल के पिता को दिल का दौरा पड़ने से जैसी समस्या हुई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। परिवार को काफी परेशानी हुई, और सफाई में कई दिन लगे।

शुक्र है बापू, तुम ना हुए !

उस पर सुबह-सुबह शांति वन पहुंच कर जो देखा, हैरान करने वाला था। बापू अपने चर्चित लंबे डग भरते हुए तेजी से वृक्षों के झुरमुट की ओर भागे से जा रहे थे। दूर से ही उनकी ओर बढ़ते हुए पूछा, इतनी सुबह उधर कहां अंधेरे की तरफ भागे जा रहे हैं और वह भी अपने पुजाने के दिन पर। साल में दो ही दिन तो आप को याद किए जाने के बचे हैं। दो अक्टूबर और तीस जनवरी। आज तो आपका नाम लेने वालों से लेकर, गोडसे का काम करने वालों तक, तमाम मढ़ाधारी आपके ठिकाने पर आने वाले हैं और आज ही आप...। बापू बिना रुके कदम बढ़ाते हुए बोले--झमेलिए तो...। इससे पहले कि यह सालाना नाटक शुरू हो, मैं कहीं निकल जाना चाहता हूं। मुझे कम से कम इस पाखंड का हिस्सा नहीं बनना है। पाखंडीपन उत्सुकता अब और जोर मारने लगी। मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा। यह कहते हुए पीछे-पीछे चलता रहा कि आप को अपनी पूजा कराने का शौक कभी नहीं था, यह तो सभी जानते हैं। दिखावे की पूजा कराने का तो हर्गिज नहीं। फिर भी आप का यह मानना अन्याय ही नहीं है कि राज करने वालों का आपकी मूर्ति पर/ तस्वीर पर फूल चढ़ाना, आपके आगे सिर झुकाना कोरा दिखावा ही है। संदेह का लाभ तो सभी को मिलना चाहिए। राज करने वाली पार्टी में सभी गोडसे भक्त थोड़े ही हैं। उनके यहां भी तो थोड़ी-बहुत वैराइटी तो होगी ही। हमें तो लगता है कि सच्चे गोडसे भक्त तो पहचान छुपाकर, जुबान चलाने वाले सोशल मीडिया हिंदू योद्धा ही ज्यादा हैं। वर्ना मोदी जी तो दुनिया में जहां भी जाते हैं, खोजकर आपकी प्रतिमा पर शीश नवाते हैं। और आप हैं कि दुनिया के ज्यादातर देशों में उन्हें मिल भी जाते हैं। फिर यह बहिष्कार...? बापू समझ गए कि आसानी से उनका पीछा नहीं छूटने वाला है। रुक कर एक पेड़ के नीचे बने टूटे-फूटे चबूतरे पर बैठ गए। इशारा कर के मुझे भी बैठने का कहा। फिर कहने लगे कि तुझे क्या लगता है कि मुझे इसकी परवाह है कि कौन वाकई मेरी पूजा करता है और कौन गोडसे की? और वह भी इसलिए कि गोडसे ने मेरे सीने पर तीन गोलियां दाग कर मेरी हत्या की थी? या मुझे इसकी परवाह है कि पिछले अठहत्तर साल में तीस जनवरी का दिन, शहादत या बलिदान दिवस से शुरू होकर, पहले पुण्यतिथि हुआ और अब सिर्फ जयंती या सालगिरह रह गया है? यहां तक कि अहिंसा दिवस, स्वच्छता दिवस, शराबबंदी दिवस, आदि में आदि में से कुछ भी। मुझे गलत मत समझना। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेशक, मुझे भी फर्क पड़ता है, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी के तौर पर मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है, देश के बापू के रूप में। मुझे फर्क पड़ता है तो इसलिए, कि इससे देश को फर्क पड़ता है। मेरे चेहरे पर मेरा प्रश्न साफ लिखा था--कैसे? बापू अपने लोकख्यात धीरज से हाथ पकड़ कर समझाने लगे। तू जो पत्रकार है, उत्तराखंड वाले ताजा किस्से का तो तुझे पता ही होगा। कहने को देवभूमि है और बड़ी तेजी से राक्षस-भूमि बनने की राह पर फिसल रही है। कोटद्वार में एक दुकान के नाम पट्ट पर लिखा है बाबा। पर उसका मालिक मुसलमान है। बस इसी का बहाना लेकर भगवाधारी झुंड बनाकर उसकी दुकान बंद कराने के लिए पहुंच गए। बाबा शब्द तो हमारा है। मुसलमान की दुकान का नाम बाबा नहीं रहने देंगे! लगे उपद्रव करने। पुलिस थी, पर हस्ब ए मामूल, तमाशा देखने की ड्यूटी पर। पर उनके तोड़-फोड़ कर पाने से पहले, दीपक नाम का एक पहलवान उनके और बाबा की दुकान के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया। एलान कर दिया कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है और न दुकान को हाथ लगाने दूंगा और न दुकानदार को। भगवाधारी झुंड ऐसी धर्मनिरपेक्षतावादी रुकावट के लिए तैयार नहीं था, पीछे लौट गया। तमाशा खत्म तो पुलिस भी घर चली गयी। पर धामी जी के राम राज्य में कहानी इतने पर खत्म कैसे हो जाती? अगले दिन भगवाई और बड़े झुंड में और पूरी तैयारी के साथ अपने धार्मिक यज्ञ में बाधा डालने वाले राक्षस, दीपक को निपटाने पहुंच गए। जी भरकर उन्हें और उनके परिवार को गालियां दीं और हंगामा किया। पुलिस एक बार फिर तमाशा देखती रही! अब जिन धामी जी की पुलिस के अशीर्वाद से आए दिन ऐसा ही कुछ न कुछ हो रहा है, वह तीस जनवरी को मुझे पूजने का स्वांग करें और मैं उनसे फूल चढ़वाऊं, अब बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने कहा पर एक के लिए सब को...? बापू ने झिड़कते हुए कहा, यह तो एक उदाहरण है। यहां तो पूरा का पूरा आवा ही बिगड़ा हुआ है। सुना नहीं असम का हिमंता बिस्व सरमा किस के नाम पर चुनाव जीतना चाहता है। इसके नाम पर कि वह मियां लोग को इतना परेशान करेगा कि देश छोड़कर भाग जाएंगे! क्या मैं उससे श्रद्धा-सुमन चढ़वाऊं? या उत्तर प्रदेश वाले योगी से, जिसका चोला साधु का, गद्दी मुख्यमंत्री की और काम...। अब तो अदालत ने भी कह दिया है कि आपरेशन लंगड़ा चलवाकर अगले ने आठ साल में 11 हजार लोगों को पांव में गोली मार कर लंगड़ा कराया है। उससे अपनी अहिंसा का सम्मान कराऊं? या ओडिशा के मांझी से, जिसके राज में बंगालियों को बाकायदा मॉब लिंचिंग में मारा जा रहा है या पुलिस द्वारा जबरन बांग्लादेश में धकेला जा रहा है। मैंने आखिरी दलील दी--पर मोदी जी? अब बापू ने थोड़ा नाराजी से घूरा! इस ब्रम्हांड को चलाने वाला कौन है? यह तो पूरे आसिकों का ब्रम्हांड है, जिसका सृष्ठ, कर्ता, संचालक, सब एक है! इसके बाद मैं क्या कहता? फिर भी उठते-उठते मैंने अपने हिसाब से चतुराई की सलाह दी। आपके गायब हो जाने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टे आप के गायबाने में ये आप की जगह पर किसी और को बापू बनाकर बैठा देंगे, पर अपने कर्म-कांड और आचार-व्यवहार, दोनों में जरा सा खलल नहीं पड़ने देंगे। बापू उठकर लंबे डग भरकर पेड़ों के झुरमुट में अदृश्य होने की ओर बढ़ते चले गए--पीछे आवाज सुनाई दी, इसीलिए तो मेरा इनसे दूर रहना और भी जरूरी है, अच्छा है!

भारत-अमेरिका समझौता

अमेरिका द्वारा भारत पर लगी हुई ऊंची 50 प्रतिशत शुल्क दर घटाकर 18 प्रतिशत कर दिये जाने से भारतीय अर्थव्यवस्था में चहुंओर लहलहाट आने की आशा जागृत हो गई है। लगभग पिछले 11 महीने से भारत व अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर वार्ता चल रही थी मगर बीच-बीच में वैश्विक राजनीतिक अस्थिरता के चलते इसमें व्यवधान पैदा हो रहे थे जिसकी वजह से वार्ता के कई दौर होने के बाद भी अमेरिका शुल्क दरें कम करने के लिए राजी नहीं हो रहा था, उल्टे इससे विगत वर्ष के सितम्बर महीने में रूस से कच्चा तेल खरीदने के नाम पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क दर लागू कर दी थी। पहले प्रतिस्पर्धी शुल्क दर 25 प्रतिशत थी जो इसके बाद बढ़कर 50 प्रतिशत हो गई थी। मगर विगत दिन लगभग 11 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की कि भारत व अमेरिका में व्यापार समझौता हो गया है जिसमें प्रतिस्पर्धी शुल्क दर को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके कुछ समय बाद ट्रम्प ने यह भी घोषणा की कि भारत रूस से तेल न खरीदने और अमेरिका व वेनेजुएला से इसे खरीदने के लिए सहमत हो गया है अतः अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क दर भी समाप्त की जाती है। श्री ट्रम्प ने कल रात ही प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी से फोन पर बात भी की।

दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते की घोषणा तब की गई है जब भारत में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट एक दिन पहले ही वित्त मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया था। बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत आर्थिक मानकों को मजबूत बनाने के साथ ही देश के हर क्षेत्र में स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उत्पादन बढ़ाने की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। अब अमेरिका के साथ व्यापार समझौता होने के बाद भारत की उत्पादन गतिविधियों में भारी उछाल आने की संभावना पैदा हो गई है जिससे वार्षिक स्तर पर विकास वृद्धि दर को भी पंख लगने की उम्मीद पैदा हो गई है। भारत अमेरिका को भारी मात्रा में निर्यात करता है और व्यापार खाता इसके पक्ष में रहता है। समझौते के बाद भारत का अमेरिका को निर्बाध निर्यात फिर से चालू हो जायेगा जिससे अर्थव्यवस्था पर चहुंओर सकारात्मक असर पड़ेगा। सबसे बड़ा असर भारत की मुद्रा रुपये की कीमत पर होने की सम्भावना है। दोनों देशों के बीच पिछले 11 महीने से बनी असमंजस की स्थिति के चलते डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर लगातार नीचे जा रही थी और पिछले छह महीने से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश लगातार घट रहा था। विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में अपने शेयरों को बेच रहे थे और संस्थागत निवेश भी घट रहा था। विगत सितम्बर महीने से लेकर अब तक विदेशी निवेशक लगभग 12 अरब डॉलर की धनराशि भारतीय बाजारों से निकाल चुके थे मगर अब इसके उल्टी दिशा में घूमने के आसार पैदा होंगे और भारतीय बाजार में विदेशी निवेश में फिर से डॉलर की प्रचुरता आयेगी। सबसे ज्यादा असर रुपये की कीमत पर पड़ने की उम्मीद है। फिलहाल डॉलर 92 रुपये के आसपास घूम रहा है। विदेशी निवेशकों के भारत में विश्वास बढ़ने की वजह से विदेशी मुद्रा डॉलर की आवक पुनः सुधरेगी जिससे रुपये की कीमत में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक पंडितों की राय में समझौते की घोषणा यूरोपीय संघ से वाणिज्य समझौता होने के बाद की गई है। इससे भारतीय उत्पादकों को भारी लाभ पहुंचेगा क्योंकि भारतीय उत्पादों की पहुंच अब यूरोप के 27 देशों तक बढ़ने के साथ ही फिर से अमेरिकी बाजारों में बेरोकटोक बढ़ जायेगी। इस प्रकार भारत दोहरे लाभ में चलने लगेगा और इसकी अर्थव्यवस्था नये आयामों को छुएगी। पिछले 11 महीने से भारत-अमेरिका के आपसी सम्बन्ध भी खासे ऊपर-नीचे हो रहे थे। इसकी मुख्य वजह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का रवैया ही था। मगर भारत ने इस मौके पर पूरी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का प्रदर्शन किया और डोनाल्ड ट्रम्प के बड़बोलेपन का जवाब नहीं दिया तथा अपना ध्यान सम्बन्धों की मधुरता को कायम रखने पर ही दिया। श्री ट्रम्प ने पिछले वर्ष भारत-पाकिस्तान के बीच हुए सैनिक संघर्ष को समाप्त कराने का श्रेय भी लेने का प्रयास किया और कई बार कहा कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम उन्हीं के प्रयासों से हुआ मगर भारत के प्रधानमन्त्री ने संसद में केवल इतना कहकर ही धुंध छांटने का काम किया कि पाकिस्तान के मामले में किसी भी विदेशी नेता से कोई बात नहीं हुई। भारत की इस नीति का हालांकि घरेलू मोर्चे पर विरोधी दलों की ओर से भारी विरोध हुआ मगर अन्ततः प्रधानमन्त्री मोदी की यही दूरदर्शिता काम आयी और अमेरिका ने वह पूरा कदम वापस लिया जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच कड़वाहट पैदा होनी शुरू हुई थी। भारत ने श्री ट्रम्प के इस बयान पर अभी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है कि वह रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा और वह इसकी भरपाई वेनेजुएला से तेल खरीद करके करेगा परन्तु इतना जरूर समझा जा रहा है कि पिछले वेनेजुएला की कार्यकारी राष्ट्रपति से श्री मोदी की फोन पर जो बात हुई थी उसमें दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार सम्बन्धों के मजबूत बनाने की सहमति हुई है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखकर चल रहा है तथा हर मोर्चे पर सन्तुलन बनाये हुए चलना चाहता है। अब अमेरिका के साथ व्यापार समझौता हो जाने के बाद भारत पूरे वैश्विक आर्थिक मामलों के केन्द्र में आ गया है और यूरोप से लेकर अमेरिका के बाजार इसके उत्पादों के लिए खुल चुके हैं। इसके साथ ही यह समझौता करके अमेरिका ने यह इशारा भी कर दिया है कि वह एशिया में चीन के मुकाबले भारत को कम महत्व नहीं देता है। चीन पर अमेरिका की शुल्क दरें 37 प्रतिशत रहेंगी जबकि ब्रिक्स के अन्य देशों में शामिल ब्राजील पर यह दर 50 प्रतिशत और दक्षिण अफ्रीका पर 30 प्रतिशत रहेगी।

सम्पादकीय...

दिल लगाना जरूरी

15 फरवरी तक बहुत ही सर्दी होने के कारण छुट्टियां है। बहुत से सदस्यों के मैसेज आ रहे है कि दिल नहीं लग रहा, जल्दी ब्रांच खोलें परन्तु क्या करें मुझे आप सबकी सेहत की चिंता है। हां यह जरूर कहूंगी कि दिल लगाना जरूरी है। अब वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के सदस्यों के आपस में बहुत से व्हट्सएप ग्रुप बन चुके है। आपस में मैसेज कीजिये, अपने विचारों का आदान-प्रदान करें। हां यही नहीं अपने शरीर को एक्टिव रखें यानी सैर और एक्सरसाइज जरूर करें। हल्का व फुल्का खाना खायें, टीवी में अच्छे-अच्छे प्रोग्राम देखें। मुझे मालूम है कि वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब में आकर आपका दिल लगता है। आज मुझे अमेरिका से हमारी सदस्य प्रेम सूद जी का फोन आया। क्योंकि उनके बच्चे उन्हें यहां अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उनका बेटा-बेटी जो अमेरिका रहते हैं उन्हें साथ लेकर गए, परन्तु एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब वो वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के सभी सदस्यों और मुझे याद न करती हों। इतना प्यार देती है कि मां जैसी लगती है। अगर कुछ दिन बीत जाए तो वो कहती है मैं तुम्हें अपने सपनों में देखती हूं। अब वो 80+ है। उनका बड़ी खुशी-खुशी से फोन आया कि मैंने अपने बच्चों को मना लिया है और मैं अपने इंडिया वापिस आ रही हूं। कुछ महीने रहूंगी। बेटी छोड़ने आ रही है, बेटा लेने आएगा। आते ही घर में पूजा करूंगी और आपने जरूर आना है। साथ में अपने कई साथियों का नाम लेकर कह रही थी कि आप प्लीज सबको सूचित कर देना। उनकी खुशी सम्भाली नहीं जा रही थी। यही नहीं हर सुबह हमारी नोएडा ब्रांच की शारदा सुशील जी का गुड मॉर्निंग और ब्लेसिंग्स का मैसेज आता है। वो भी 80+ है, परन्तु उनकी बेटी जो उनका बहुत ख्याल रखती है, उन्हें ब्रांच और फंक्शन में लेकर आती है और हमारी पंजाबी बाग की एक और सदस्य जो 80+है, जिनकी दो बेटियां है एक अमेरिका और एक लंदन में, वो भी उन्हें साथ लेकर गईं। बहुत ख्याल रखती है, परन्तु उनका भी बाहर दिल नहीं लगा वो भी वापिस आकर गुड़गांव के पास कोई स्थान है वहां रह रही है। उनकी बेटियां भी मेरे सम्पर्क में रहती है। हमेशा मुझे धन्यवाद करती है कि वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के कारण हमारी मां में नई चुस्ती-स्फूर्ति है, जीने की चाह है। मां अक्सर वीडियो बनाती रहती है (जो हमने वरिष्ठ नागरिक के प्लेटफार्म पर सिखाई है) यह तो मैं कुछ गिने-चुने लोगों की खुशियां बता रही हूं, परन्तु ऐसे बहुत से सदस्य है। यही नहीं हमारी पश्चिम विहार की शाखा अध्यक्ष पंजाबी बाग, ग्रीन पार्क, नोएडा, जी.के.-II, गुड़गांव के शाखा अध्यक्ष सभी पहले दिन से जुड़े है। फरीदाबाद के शाखा अध्यक्ष कस्तूरिया जी जटवानी जी ने अपने को मार्गदर्शक बनाकर पुष्पानी जी और सुषमा को आगे कर दिया। ऐसे ही मॉडल टाऊन की अध्यक्ष मंजू जी ने बीनू चौहान को आगे कर दिया है। गुजरांवाला टाऊन की शाखा को स्वर्गीय भोला नाथ विज जी की बहू और गीता नैय्यर चला रही है। हैदराबाद की शाखा में हर्ष जी ने मीना मूथा जी को आगे कर दिया है। कई शाखाएं पाइप लाइन में है। कुल मिलाकर पिछले 22 सालों से हम परिवार की तरह आगे बढ़ रहे है।

राष्ट्रीय सुरक्षा और राहुल गांधी की राजनीतिक अपरिपक्वता

नीति-निर्माण, राष्ट्रीय सुरक्षा और संसदीय विमर्श जैसे गंभीर विषय किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं। संसद केवल सत्ता और विपक्ष के टकराव का मंच नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता, सामूहिक विवेक और जिम्मेदार अभिव्यक्ति का सर्वोच्च स्थल है। ऐसे में जब राष्ट्रपति के अभिभाषण जैसे संवैधानिक और गरिमामय अवसर पर चर्चा चल रही हो, तब किसी भी नेता से यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि वह शब्दों, संदर्भों और समय-तीनों के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरते। हालिया घटनाक्रम में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के कुछ अंशों का हवाला देकर चीनी सेना की कथित घुसपैठ को लेकर जो बयान दिया गया, उसने इसी अपेक्षा पर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए। सरकार का आरोप रहा कि इस बयान ने लोकसभा को गुमराह करने का प्रयास किया, जबकि विपक्ष ने इसे सच दबाने की कोशिश बताकर पलटवार किया। परिणाम यह हुआ कि संसद की कार्यवाही बाधित हुई, तीखी बहस ने पूरे दिन का सत्र स्थगित करा दिया और राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र मूल मुद्दों से हटकर आरोप-प्रत्यारोप बन गया। यह प्रश्न केवल एक वक्तव्य का नहीं, बल्कि राजनीतिक परिपक्वता, जिम्मेदारी और राष्ट्रीय हित की समझ का है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर सार्वजनिक वक्तव्यों में संवेदनशीलता अनिवार्य होती है। सीमाओं से जुड़े तथ्य, सैन्य तैनाती, रणनीतिक आकलन-ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर आधे-अधूरे संदर्भ या चयनित उद्धरण अनावश्यक भ्रम पैदा कर सकते हैं। यही कारण है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने इसे संसदीय नियमों के उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ बताया। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था देने के बावजूद यदि किसी नेता का अपने वक्तव्य पर अड़े रहना कार्यवाही को ठप कर दे, तो सवाल उठता है कि क्या उद्देश्य सच सामने लाना था या राजनीतिक लाभ साधना। विपक्ष का दायित्व सत्ता से सवाल करना है, यह लोकतंत्र का प्राण है। किंतु सवालों

की भाषा, मंच और समय-तीनों लोकतांत्रिक मर्यादाओं से बंधे होते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का समय सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और भविष्य की दिशा पर समग्र विमर्श का होता है। उस दौरान सैन्य पुस्तकों के चयनित अंशों को राजनीतिक हथियार बनाना, वह भी बिना समुचित संदर्भ और संस्थागत प्रक्रिया के, स्वाभाविक रूप से विवाद को जन्म देता है। विपक्ष का यह कहना कि सरकार असहज प्रश्नों को दबाना चाहती है, एक परिचित एवं बेतुका राजनीतिक तर्क है, परंतु सरकार का यह कहना कि राष्ट्रीय सुरक्षा को राजनीतिक रंग देना अनुचित है, उतना ही वजनदार प्रतिवाद है। दोनों पक्षों के बीच संतुलन वहीं संभव है, जहां तथ्य, प्रक्रिया और समय का सम्मान हो। संसद के भीतर अप्रकाशित 'संस्मरण' के जिक्र पर विवाद होना स्वाभाविक है। क्योंकि संसदीय परंपराओं और स्थापित नियमों के अनुसार किसी भी सदस्य द्वारा संसद के पटल पर ऐसी प्रकाशित या अप्रकाशित पुस्तक, लेख या पत्रिका की सामग्री को प्रमाण के रूप में उद्धृत करना स्वीकार्य नहीं है, जिसे सदन के समक्ष औपचारिक रूप से प्रस्तुत (टेबल) न किया गया हो। विशेष रूप से ऐसी पुस्तकों या लेखों के अंश, जिनकी न तो संसदीय सत्यापन प्रक्रिया हुई हो और न ही जिन्हें सदन की अनुमति से अभिलेखित किया गया हो, उन्हें तथ्यात्मक प्रमाण मानना संसदीय मर्यादा के विरुद्ध है। इस दृष्टि से राहुल गांधी द्वारा किसी अप्रकाशित पुस्तक के अंशों को सीधे उद्धृत कर उन्हें नीतिगत या राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर अंतिम सत्य के रूप में प्रस्तुत करना न केवल संसदीय नियमों की अवहेलना है, बल्कि इससे सदन की गरिमा और कार्यवाही की विश्वसनीयता भी आहत होती है। राहुल गांधी केवल कांग्रेस के नेता ही नहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है। कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में तो उन्हें भारतीय सेनाओं के नैरेटिव के साथ खड़े होना चाहिए।

दुर्भाग्य से वे ऐसा नहीं करते। वे चीन और पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार को तो घेरते हैं, लेकिन यह स्मरण नहीं रखते कि इन दोनों देशों ने भारतीय भूभाग पर तब अतिक्रमण किया, जब कांग्रेस सत्ता में थी। गलवान में चीनी सेना के साथ खूनी टकराव के मामले में तत्कालीन सेनाध्यक्ष की अप्रकाशित पुस्तक के कथित अंश का जैसा उल्लेख राहुल गांधी ने किया, उस पर हंगामा होना ही था। आखिर जो पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई, उसका उल्लेख राहुल कैसे कर सकते हैं? राहुल गांधी का आरोप कि मोदी सरकार ने चीनी सेना के अतिक्रमणकारी रवैये पर साहस नहीं दिखाया, बेबुनियाद एवं भ्रमित करने वाला आरोप है। यह पहली बार नहीं है, जब राहुल गांधी ने यह कहने की कोशिश की हो कि प्रधानमंत्री मोदी चीन का डटकर मुकाबला करने से बचते हैं। वे मोदी सरकार को कमजोर दिखाने के लिए यह भी कहते रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। वे यहां तक कह चुके हैं कि चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों की पिटाई की थी। इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी सुननी पड़ी थी। इसके बाद भी वे यह समझने के लिए तैयार नहीं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सतही आरोपों के आधार पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जबकि सच्चाई यह है और सब जानते है कि गलवान में चीनी सेना को करारा जवाब मिला था और इसी कारण वह वार्ता की मेज पर आया और लद्दाख में कई इलाकों में यथास्थिति कायम हो पाई। कांग्रेस की भूमिका पर भी गंभीर आत्ममंथन आवश्यक है। एक समय देश को नेतृत्व देने वाली पार्टी आज बार-बार ऐसे प्रसंगों में उलझती दिखती है, जहां बयानबाजी मुद्दों पर भारी पड़ जाती है। राहुल गांधी एक प्रभावशाली वक्ता हैं, जनभावनाओं को छूने की क्षमता रखते हैं और युवाओं में संवाद स्थापित कर सकते हैं। किंतु यही कारण है कि उनसे अधिक जिम्मेदारी की अपेक्षा भी की जाती है। बार-बार ऐसे मुद्दे उठाना जिन्हें सत्ता पक्ष राष्ट्रीय एकता के लिए घातक बताता हो, कांग्रेस की छवि को गैर-जिम्मेदार विपक्ष के रूप में मजबूत करता है। यह धारणा चाहे पूरी तरह सही न हो, लेकिन राजनीति में धारणा भी उतनी ही प्रभावशाली होती है जितना तथ्य। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो परिपक्व लोकतंत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहस के लिए अलग-अलग संसदीय समितियां, बंद सत्र और संस्थागत प्रक्रियाएं होती हैं। सार्वजनिक मंचों पर बयान देते समय नेता प्रायः संकेतों और नीतिगत प्रश्नों तक सीमित रहते हैं, विस्तृत सैन्य विवरणों से परहेज करते हैं। भारत में भी ऐसी परंपरा विकसित होनी चाहिए, जहां विपक्ष सरकार से जवाबदेही मांगे, परंतु सेना और सुरक्षा संस्थानों की साख को राजनीतिक संघर्ष का अखाड़ा न बनाया जाए। यही संतुलन लोकतंत्र को मजबूत करता है। लेकिन राहुल गांधी पूर्व में भी सैन्य बयानों से न केवल सुरक्षा के लिए खतरा बनते रहे है बल्कि हमारे जवानों के मनोबल को भी आहत करते रहे है। यह भी सच है कि सरकार को पारदर्शिता से भागना नहीं चाहिए। यदि विपक्ष किसी पुस्तक, रिपोर्ट या बयान का हवाला देता है, तो उसका संस्थागत और तथ्यपरक उत्तर दिया जाना चाहिए। केवल नियमों के उल्लंघन का हवाला देकर बहस को समाप्त करना भी स्वस्थ परंपरा नहीं कही जा सकती। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर पूर्ण मौन भी लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के विपरीत है। अतः दोनों पक्षों को अपनी-अपनी सीमाएं पहचाननी होंगी। अंततः प्रश्न राहुल गांधी की परिपक्वता का भी है। परिपक्वता का अर्थ चुप रहना नहीं, बल्कि यह समझना है कि कौन-सा प्रश्न कब, कहां और कैसे उठाया जाए। एक राष्ट्रीय नेता से अपेक्षा होती है कि वह भावनात्मक आवेग के बजाय रणनीतिक विवेक से काम ले। इसी तरह विपक्ष की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वह संसद को ठप करने के बजाय उसे प्रभावी बहस का मंच बनाए। संसद का स्थगन किसी की जीत नहीं, बल्कि लोकतंत्र की हार होता है। इस पूरे प्रसंग ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि भारत जैसे विविध और संवेदनशील लोकतंत्र में शब्दों की शक्ति अत्यंत गहरी है। राष्ट्रीय एकता केवल सीमाओं की रक्षा से नहीं, बल्कि जिम्मेदार राजनीति से भी सुरक्षित रहती है। कांग्रेस को यह सोचना होगा कि क्या तात्कालिक राजनीतिक लाभ दीर्घकालिक विश्वसनीयता से अधिक महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी को यह आत्मविश्लेषण करना होगा कि नेतृत्व केवल सवाल उठाने से नहीं, बल्कि मर्यादित और समयबद्ध विवेक से भी बनता है। और सरकार को यह याद रखना होगा कि मजबूत राष्ट्र वही है जो सवालों से नहीं, बल्कि जवाबों से मजबूत होता है। यदि यह संतुलन स्थापित हो सका, तभी संसद का प्रत्येक सत्र वास्तव में राष्ट्र के हित में सार्थक सिद्ध होगा।

व्हाट्सऐप-मेटा, डीपीडीपी एक्ट 2023 और भारतीय संविधान की ऐतिहासिक टकराहट

वैश्विक स्तरपर भारत इक्कीसवीं सदी में केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार नहीं रहा,बल्कि वह अब डिजिटल लोकतंत्र, डेटा संप्रभुता और नागरिक निजता के वैश्विक विमर्श का केंद्र बन चुका है।करोड़ों भारतीय नागरिकों का डिजिटल जीवन,उनकी बातचीत स्वास्थ्य जानकारी,आर्थिक लेन- देन,सामाजिक व्यवहार और वैचारिक झुकाव अब तकनीकी प्लेटफॉर्मों के सर्वरों में दर्ज हो रहा है। ऐसे समय में यह प्रश्न केवल तकनीकी या व्यावसायिक नहीं रह जाता,बल्कि सीधे-सीधे संविधान, मानवाधिकार और राज्य की संप्रभु जिम्मेदारी से जुड़ जाता है। डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण अधिनियम (डीपीडीपी एक्ट), 2023 इसी ऐतिहासिक जरूरत की उपज है, जो यह स्पष्ट करता है कि भारत में किसी भी नागरिक का डेटा अब अनियंत्रित कॉर्पोरेट शक्ति के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि डीपीडीपी अधिनियम 2023 का मूल उद्देश्य केवल डेटा चोरी रोकना नहीं है,बल्कि यह नागरिकों को यह अधिकार देता है कि उनका डिजिटल अस्तित्व भी उतना ही सुरक्षित हो,जितना उनका भौतिक अस्तित्व। यह कानून स्पष्ट करता है कि डेटा किस उद्देश्य से,कितनी सीमा तक और कितनी अवधि के लिए प्रोसेस किया जा सकता है।यह अधिनियम सूचित सहमति को केंद्रीय तत्व बनाता है,ताकि कोई भी कंपनी चाहे वह भारत की हो या विदेशी,यूजर को मानो या छोड़ो जैसी शर्तों में फँसाकर उसकी निजता का सौदा न कर सके। इस दृष्टि से भारत पहली बार डेटा को केवल आर्थिक संसाधन नहीं,बल्कि संवैधानिक अधिकार के रूप में स्थापित करता दिखता है। इसी पृष्ठभूमि में व्हाट्सऐप और उसकी पैरेंट कंपनी मेटा का मामला केवल एक कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी तक सीमित नहीं रह जाता,बल्कि यह प्रश्न बन जाता है कि क्या वैश्विक टेक कंपनियाँ भारतीय संविधान के दायरे में काम करने को तैयार हैं या नहीं। वर्ष 2021 में व्हाट्सऐप द्वारा लाई गई टेक इट और लीव इट प्राइवेसी पॉलिसी ने भारतीय यूजर्स को दो ही विकल्प दिए, या तो नई शर्तें स्वीकार करें या सेवा छोड़ दें। यह नीति न केवल असमान शक्ति-संतुलन का उदाहरण थी,बल्कि इसने नागरिकों की वास्तविक सहमति की अवधारणा को भी खोखला कर दिया।भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (एनसीएलएटी) ने नवंबर 2024 में इस नीति को प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन मानते हुए मेटा पर 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। आयोग का स्पष्ट मत था कि व्हाट्सऐप ने अपनी डॉमिनेंट पोजिशन का दुरुपयोग करते हुए यूजर्स को ऐसी शर्तें मानने के लिए मजबूर किया, जिनका व्यावसायिक लाभ सीधे मेटा के विज्ञापन मॉडल को जाता था। यह जुर्माना केवल आर्थिक दंड नहीं था, बल्कि यह एक नियामकीय संदेश था कि भारत में डिजिटल बाजार अब फ्री-फॉर-ऑल नहीं रहेगा। हालाँकि,जनवरी 2025 में एनसीएलएटी ने एक विरोधाभासी रुख अपनाया।उसने डॉमिनेंस के दुरुपयोग वाले निष्कर्ष को हटाते हुए भी जुर्माने को बरकरार रखा। यह निर्णय कानूनी दृष्टि से जटिल था,क्योंकि यदि डॉमिनेंस का दुरुपयोग नहीं हुआ, तो फिर जुर्माने का आधार क्या है यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है। इसी कानूनी असंगति को चुनौती देते हुए मेटा सुप्रीम कोर्ट पहुँची,लेकिन शायद उसे यह अनुमान नहीं था कि यह मामला केवल प्रतिस्पर्धा कानून तक सीमित नहीं रहेगा,बल्कि सीधे भारतीय संविधान की आत्मा से टकराएगा।मंगलवार, 3 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई ने इस विवाद को ऐतिहासिक मोड़ दे दिया। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने जिस कठोरता और स्पष्टता से व्हाट्सएप-मेटा की प्राइवेसी प्रैक्टिस पर सवाल उठाए,उसने यह संकेत दे दिया कि अब अदालत इस मामले को केवल कॉर्पोरेट नीति के रूप में नहीं देख रही। साथियों बात अगर हम 3फरवरी 2026 को हुई सुनवाई को गहराई से समझने की करें तो केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर ने जब यह तर्क रखा कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी शोषणकारी है और यूजर्स के डेटा का व्यावसायिक उपयोग करती है,तब अदालत की प्रतिक्रिया असाधारण रूप से सख्त थी।मुख्य न्यायाधीश का कथन अगर हमारे संविधान का पालन नहीं कर सकते तो भारत छोड़कर जाइए किसी भी वैश्विक टेक कंपनी के लिए अब तक की सबसे तीखी न्यायिक चेतावनी मानी जा सकती है।यह कथन केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं था,बल्कि यह भारत की डिजिटल संप्रभुता की स्पष्ट घोषणा थी। अदालत ने यह रेखांकित किया कि कोई भी सेवा प्रदाता भारत में व्यापार तभी कर सकता है, जब वह भारतीय संविधान, मौलिक अधिकारों और नागरिकों की गरिमा का सम्मान करे।अदालत ने यह भी कहा कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी इतनी चालाकी से तैयार की गई है कि एक आम नागरिक चाहे वह गरीब बुजुर्ग महिला हो,सड़क किनारे वेंडर हो या केवल तमिल बोलने वाली ग्रामीण महिला उसके निहितार्थ कभी समझ ही नहीं सकती। यह टिप्पणी भारत की सामाजिक-आर्थिक विविधता को केंद्र में रखती है और यह स्वीकार करती है कि सूचित सहमति केवल अंग्रेजी में लिखे लंबे दस्तावेज से नहीं आती सहमति तभी वास्तविक मानी जाएगी, जब यूजर को पूरी तरह यह समझ हो कि उसका डेटा कैसे,क्यों और किसके साथ साझा किया जा रहा है। साथियों बात अगर हम इस सुनवाई को और गहराई से समझने की करें तो सुनवाई के दौरान पीठ के अन्य माननीय जस्टिस ने बहस को और गहराई देते हुए कहा कि डीपीडीपी एक्ट भले ही प्राइवेसी की बात करता हो, लेकिन असली चिंता यूजर्स की बिहेवियरल टेंडेंसीज को लेकर है। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह प्रश्न उठाया कि जब डिजिटल फुटप्रिंट का उपयोग ऑनलाइन विज्ञापन और माइक्रो-टार्गेटिंग के लिए किया जा रहा है, तब यह केवल प्राइवेसी का मुद्दा नहीं रह जाता,बल्कि यह मानव व्यवहार के व्यावसायिक दोहन का मामला बन जाता है।यहटिप्पणी वैश्विक स्तर पर फेसबुक- कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसे घोटालों को याद दिलाती है, जहाँ डेटा का उपयोग लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने तक में किया गया।मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं का उदाहरण देते हुए बताया कि जैसे ही कोई डॉक्टर व्हाट्सएप पर दवाइयों के नाम भेजता है, कुछ ही मिनटों में उन्हीं दवाओं के विज्ञापन दिखने लगते हैं। यह उदाहरण इस बात की ओर इशारा करता है कि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के दावों के बावजूद, मेटाडेटा और व्यवहारिक संकेतों का उपयोग किस हद तक व्यावसायिक प्रोफाइलिंग में किया जा रहा है। यह सवाल केवल तकनीकी नहीं, बल्कि नैतिक और कानूनी भी है।मेटा के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सीमित डेटा शेयरिंग की अनुमति है और कंपनी की नीतियाँ अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। लेकिन अदालत ने इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश की यह टिप्पणी अगर आपको डेटा का कोई भी हिस्सा बेचने लायक लगेगा, तो आप उसे बेच देंगे?कॉर्पोरेट मंशा पर सीधा प्रश्नचिह्न लगाती है? अदालत ने यह भी कहा कि भारतीय उपभोक्ताओं की चुप्पी को उनकी सहमति नहीं माना जा सकता। साथियों बात अगर हम पूरे विवाद के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में समझने की करें तो यह और भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूरोप का जीडीपीआर,अमेरिका में राज्य-स्तरीय डेटा कानून और अब भारत का डीपीडीपी एक्ट ये सभी संकेत देते हैं कि दुनिया अब डेटा फ्री मार्केट से डेटा गवर्नेंस की ओर बढ़ रही है।भारत,अपने विशाल यूजर बेस और लोकतांत्रिक मूल्यों के कारण,इस परिवर्तन में नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की यह सख्त भूमिका यह संदेश देती है कि भारत केवल कानून बनाकर नहीं, बल्कि उन्हें लागू कराकर भी डिजिटल अधिकारों की रक्षा करेगा। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि अब यह मामला केवल व्हाट्सऐप या मेटा का नहीं है। यह सवाल है कि डिजिटल युग में नागरिक की गरिमा,निजता और स्वायत्तता को कौन परिभाषित करेगा कॉर्पोरेट एल्गोरिद्म या लोकतांत्रिक संविधान। 9 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई और तीन- जजों की बेंच का निर्णय भारत के डिजिटल भविष्य की दिशा तय कर सकता है।यदि अदालत नागरिकों के पक्ष में सख्त मानक तय करती है, तो यह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया डेटा-न्याय मॉडल प्रस्तुत करेगा।यह संघर्ष दरअसल डेटा साम्राज्यवाद और संवैधानिक संप्रभुता के बीच है। और इस बार, संकेत स्पष्ट हैं भारतीय संविधान

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने करना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, सादत पैपरवाला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/...)

पीड़ित महिलाओं ने आयोग की सदस्या को सुनाया दुखड़ा

जिला अस्पताल, महिला थाने और जेल का किया निरीक्षण

मुरादाबाद।

राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता जैन ने मुरादाबाद के सर्किट हाउस में महिला जनसुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में पीड़ित महिलाएं उपस्थित रहीं और उन्होंने उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर शिकायतें दर्ज कराईं। सदस्या ने जिला महिला चिकित्सालय, महिला थाना, सिविल लाइन थाना और जिला कारागार का निरीक्षण किया। जनसुनवाई के दौरान संगीता जैन ने महिलाओं की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कई मामलों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई कर पीड़ित महिलाओं को जल्द न्याय दिलाने के निर्देश दिए गए। जिला प्रोबेशन अधिकारी चंद्र भूषण ने बताया कि यह जनसुनवाई राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता जैन की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। इसमें महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों की सुनवाई की जा रही है और शिकायतों को दर्ज कर समाधान की प्रक्रिया शुरू की गई है। जनसुनवाई में घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, पारिवारिक कलह, मारपीट और महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कई मामले सामने आए। आयोग की सदस्य ने महिलाओं को आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। रा'य महिला आयोग द्वारा आयोजित इन जनसुनवाइयों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को न्याय दिलाना, उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना और समाज में महिलाओं के प्रति अत्याचार को रोकना है।

टीएमयू नर्सिंग छात्रों को हार्ट अटैक में बचाव को दी सीपीआर की ट्रेनिंग

मुरादाबाद।

तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद के कॉलेज ऑफ नर्सिंग के मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग विभाग की ओर से प्राथमिक चिकित्सा और कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन-सीपीआर ए हैंड्स-ऑन इमरजेंसी रिस्पांस पर दो दिनी वर्कशॉप में जीवन रक्षक सीपीआर तकनीक और आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा का सघनता से प्रशिक्षण दिया गया। इससे पूर्व नर्सिंग कॉलेज की डीन प्रो. एसपी सुभाषिनी और प्रधानाचार्या डॉ. जेसलीन एम. ने मां सरस्वती के समक्ष प्र'ज्वलित करके वर्कशॉप का शुभारम्भ किया। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के विभागाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बतौर मुख्य वक्ता जीवन रक्षक सीपीआर तकनीक पर बोलते हुए कहा, जिन व्यक्तियों की दिल की धड़कन रुक गई हो या जिन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा हो, उन्हें बचाने के लिए सीपीआर महत्वपूर्ण है। तकनीकी सत्र में डमी पर सीपीआर का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों और छात्रों ने इन तकनीकों का पुनः अभ्यास किया। फैकल्टी नफीस अहमद और ट्यूटर मीनाक्षी गंगवार ने प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण पर बोलते हुए कहा, सांप के काटने, शीत दंश / ठंड से बचाव, कुत्ते के काटने, घावों, आंख में बाहरी वस्तु जाने और नाक से खून बहने (नकसीर) आदि विभिन्न आपात स्थितियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा के महत्व और तरीकों को विस्तार से समझाया। इन विशेषज्ञों ने प्राथमिक चिकित्सा में उपयोग होने वाली वस्तुओं को दिखाते हुए प्रदर्शन के जरिए इसके व्यावहारिक लाभों को समझाया। वर्कशॉप में एनएसएस समन्वयक गौरव कुमार के संग-संग बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग समेत स्वीपिंग स्टॉफ शामिल रहा। इस वर्कशॉप में एनएसएस की भी उल्लेखनीय भूमिका रही। अंत में करिश्मा सिंह ने सभी का धन्यवाद दिया।

बहराइच में यूनाइटेड फॉर यूनीक की थीम पर मनाया गया विश्व कैंसर दिवस

बहराइच।

विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय सभागार में यूनाइटेड फॉर यूनीक की थीम पर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. संजय कुमार की अध्यक्षता में गोष्ठी, स्क्रीनिंग शिविर तथा हस्ताक्षर अभियान संचालित किया गया। गोष्ठी को सम्बोधित करते हुए सीएमओ डॉ. कुमार ने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को रोकथाम, समय पर पहचान, सही इलाज और इससे जुड़ी गलतफहमियों को दूर करने के उद्देश्य से ही यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कैंसर से बचाव के लिए स्वस्थ जीवनशैली, नियमित जांच और मादक पदार्थों की रोकथाम बहुत ज़रूरी है ताकि इस बीमारी से होने वाली मौतों को कम किया जा सके और जीवन बचाया जा सके।

गोष्ठी, स्क्रीनिंग शिविर के साथ संचालित हुआ हस्ताक्षर अभियान

सीएमओ ने कहा कि शरीर में कोशिकाओं के समूह की अनियंत्रित वृद्धि कैंसर है। जब ये कोशिकाएं टिश्यू को प्रभावित करती हैं तो कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाता है। कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है। लेकिन यदि कैंसर का सही समय पर पता ना लगाया गया और उसका उपचार ना हो तो इससे मौत का जोखिम बढ़ सकता है। उन्होंने बताया कि कैंसर जैसे रोग के प्रति लोगों में जनजागरूकता के उद्देश्य से समस्त स्वास्थ्य इकाइयों पर विश्व कैंसर दिवस से सम्बन्धित कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। एनसीडी कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. संदीप मिश्रा ने कहा कि आजकल फल और सब्जियों में बेतहाशा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है। पीने का पानी भी पूरी तरह शुद्ध नहीं है। जिसका सीधा असर शरीर पर पड़ रहा है। पहले कैंसर बुजुर्गों की बीमारी मानी जाती थी, लेकिन अब युवा और मध्यम आयु वर्ग तेजी से इसकी चपेट में आ रहा है। मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. विजित जायसवाल ने कहा कि हम सभी जानते ही हैं कि हमारे शरीर में कई प्रकार की कोशिकाएं होती है लेकिन जब ये कोशिकाएं बढ़ जाती हैं और अनियन्त्रित हो जाती हैं एवं शरीर के हिस्सों को काम करने में दिक्कत देती है और उन हिस्सों पर कोशिकाओं का गुच्छा सौम्य गाँठ या ट्यूमर बन जाता है और बढ़ता रहता है इस अवस्था को ही कैन्सर कहते हैं। कार्यक्रम का संचालन कर रहे कैंसर विभाग के नोडल अधिकारी डॉ. परितोष तिवारी ने कहा कि लोगों को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के बारें में अवगत कराने के लिए विश्व कैन्सर दिवस हर वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। ताकि लोगों को कैंसर के होने वाले नुकसान के बारे में बताया जा सकें और लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जा सकें। उन्होंने कहा कि कैंसर के सौ से भी अधिक रूप है। जैसे- स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेन कैंसर, बोन कैंसर, ब्लैडर कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, गर्भाशय कैंसर, किडनी कैंसर, लंग कैंसर, त्वचा कैंसर, स्टमक कैंसर, थायरॉड कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर इत्यादि। एनसीडी क्लीनिक के फिजिशियन डॉ. अंशुमान सिंह श्रीनेत्र ने बताया कि कैंसर सेल्स सबसे पहले शरीर को संक्रमण से बचाने वाले हिस्से में फलती है और उसके बाद खून के रास्ते शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाती है और उन्हें संक्रमित करती है। जिला स्वास्थ्य शिक्षा सूचनाधिकारी बृजेश सिंह ने कहा कि यदि आप कैंसर से बचना चाहते है तो आपको अपनी जीवनशैली नियंत्रित करनी होगी और अपने खानपान पर विशेष ध्यान देना होगा। इस अवसर पर उपभोक्ता फोरम के न्यायाधीश सुरेश चन्द्र भारती, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष राना कुमार, उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अनुराग वर्मा, डॉ. ए. श्रीवास्तव, डॉ. निर्मेष, डॉ. रियाजुल हक, डॉ. एस.जे. हुसैन, डॉ. एम.एम. जाफरी, डॉ. एस.के. तिवारी, डॉ. आकिब, एफएलसी विवेक श्रीवास्तव, एम. एंड ई. मुकेश कुमार हंस, डीईओ मोहम्मद हारून व शरद श्रीवास्तव सहित एनसीडी क्लीनिक से जिला सलाहकार पुनीत शर्मा, लैब टेक्नीशियन सन्तोष सिंह, स्टाफ नर्स बृज प्रकाश व स्वाती श्रीवास्तव, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम से सोशल वर्कर हरीश कुमार, कम्युनिटी नर्स सीमा कुमारी, अजय प्रताप सिंह, मनीष कुमार सिंह सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण विधि से कराया गया रूबरू

प्रशिक्षण का उद्देश्य, नवीन तकनीकों से शिक्षकों को सशक्त बनाना-आरती गुप्ता

फतेहपुर।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) फतेहपुर में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सामाजिक विज्ञान शिक्षकों के लिए आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का मंगलवार को सफलतापूर्वक समापन हो गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 31 जनवरी से 03 फरवरी 2026 तक चला, जिसमें जनपद भर से आए सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन डायट की प्राचार्य एवं उप शिक्षा निदेशक आरती गुप्ता के कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में किया गया। समापन अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को नवीन एवं प्रभावी शिक्षण तकनीकों से सशक्त बनाना है, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण शिक्षकों की अकादमिक गुणवत्ता, कार्यकुशलता एवं नवाचार क्षमता को निरंतर मजबूत करते हैं। प्रशिक्षण सत्रों के दौरान शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण विधियों, कक्षा-कक्ष में प्रभावी प्रस्तुतीकरण, पाठ्यवस्तु की सरल, रोचक एवं व्यावहारिक व्याख्या तथा छात्र-केंद्रित शिक्षण पद्धतियों की विस्तृत जानकारी दी गई। सत्रों में शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी रही और अनुभव साझा किए गए। प्रशिक्षण प्रदान करने में अशोक कुमार शर्मा, भागवत शरण, कुलदीप कुमार (सहायक अध्यापक) एवं कौशल कुमार अंकुर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहीं कार्यक्रम के सफल संचालन में विनय कुमार मिश्र (सेवारत प्रशिक्षण प्रभारी) ने प्रशिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया एवं सत्रों का प्रभावी संचालन करते हुए शिक्षकों को समस्याओं के समाधान उन्मुख दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम को जिला विद्यालय निरीक्षक, फतेहपुर राकेश कुमार का विशेष सहयोग एवं मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता और प्रभावशीलता और अधिक सुदृढ़ हुई। समापन अवसर पर प्रतिभागी शिक्षकों ने प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी एवं व्यवहारिक बताते हुए भविष्य में भी इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने की अपेक्षा जताई। सभी प्रतिभागी शिक्षकों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्रशिक्षण के उपरांत शिक्षकों ने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से अपना फीडबैक भी प्रस्तुत किया। डायट फतेहपुर में आयोजित यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जनपद में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को नई दिशा देने वाला साबित हुआ।

शिविर में रेल कर्मियों एवं परिजनों की जांची गई सेहत

मुरादाबाद।

विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर मंडल चिकित्सालय, मुरादाबाद में रेलवे कर्मचारियों एवं उनके परिजनों के लिए एक वृहद कैंसर जांच एवं जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना, इसकी समय पर पहचान सुनिश्चित करना तथा उचित उपचार के महत्व को रेखांकित करना था। शिविर में उजाला सिग्नस ब्राइटस्टार चिकित्सालय, मुरादाबाद से आमंत्रित दो वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञों द्वारा लाभार्थियों को कैंसर के प्रारंभिक लक्षणों, संभावित कारणों, जोखिम कारकों तथा रोकथाम के उपायों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई। विशेषज्ञों ने नियमित स्वास्थ्य जांच, संतुलित जीवनशैली एवं किसी भी संदिग्ध लक्षण की स्थिति में शीघ्र चिकित्सकीय परामर्श लेने पर विशेष बल दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारी एवं लाभार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। शिविर के दौरान प्रतिभागियों को आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श प्रदान किया गया तथा उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग एवं जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया गया। मंडल चिकित्सालय के अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार के स्वास्थ्य जागरूकता एवं जांच कार्यक्रमों से कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार होता है तथा गंभीर बीमारियों की प्रारंभिक अवस्था में पहचान संभव हो पाती है। कार्यक्रम का समापन सफलतापूर्वक हुआ, जिसमें सभी उपस्थित जनों ने स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और नियमित स्वास्थ्य जांच कराने का संकल्प लिया।

विश्व कैंसर दिवस पर टीएमयू हॉस्पिटल में अवेयरनेस कैंपेन

मुरादाबाद। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद के तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के सामुदायिक चिकित्सा विभाग की ओर से विश्व कैंसर दिवस पर टीएमयू अस्पताल में सामान्य और प्रचलित कैंसरों जैसे- मुख कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, स्तन कैंसर, जठरांत्र- गैस्ट्रो-इंटेस्टाइनल तंत्र के कैंसर आदि को लेकर अवेयरनेस कैंपेन चला। इस अवेयरनेस कैंपेन का नेतृत्व मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रो. एनके सिंह, सामुदायिक चिकित्सा विभाग की एचओडी डॉ. साधना सिंह, डॉ. शिल्पा रेड्डी, डॉ. ऋषि शर्मा के संग-संग एमबीबीएस इंटर्न बैच की टीम ने किया। इस टीम ने टीएमयू अस्पताल में पोस्टर, मॉडल और एक्सटेम्पोर प्रस्तुतियों के जरिए लोगों को जागरूक किया। जागरूकता कार्यक्रम में ईंनटी के एचओडी प्रो. प्रबल चटर्जी, ओबीजी की एचओडी डा. मनप्रीत कौर के अलावा नर्सिंग, पैरामेडिकल, मेडिकल स्टाफ और विभिन्न विभागों के मरीजों, तीमारदार आदि मौजूद रहे।

पंचायत चुनाव मामला: हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सुक्खू सरकार

नई दिल्ली। हिमाचल सरकार ने प्रदेश में 30 अप्रैल से पहले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को करवाने को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट के 9 जनवरी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसे लेकर शीर्ष अदालत में एक अपील याचिका दायर की गई है, जिस पर अब सुनवाई होगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के महाधिवक्ता अनूप रत्न ने बताया कि रोस्टर को जारी करने के बाद आपत्तियों को लेकर खंडपीठ की अलग-अलग राय सामने आई है। उन्होंने कहा कि कानून की व्याख्या को स्पष्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन मुख्य रूप से दो बिंदुओं को लेकर दायर की गई है। पहला, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को पंचायती चुनाव संस्थाओं का रोस्टर जारी करने के लिए केवल चार दिनों का समय दिया है, जोकि तर्कसंगत और न्याय संगत नहीं है। जबकि एक अन्य खंडपीठ ने 2021 में मनीष धर्मैक मामले में रोस्टर जारी करने के बाद आपत्तियों को सुनने के लिए तीन महीनों का समय दिया है। पंचायती चुनाव को समय पर करवाने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करने वाली खंडपीठ ने इस फैसले पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। वहीं, दूसरा महत्वपूर्ण सवाल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से संबंधित है। प्रदेश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू होने पर क्या पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के प्रावधानों को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है या नहीं। इस पर भी कानून की स्थिति स्पष्ट होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट केंद्र सरकार का अधिनियम है, जबकि पंचायती राज अधिनियम राज्यों का है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को टालने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। 31 जनवरी को पंचायती संस्थानों का कार्यकाल खत्म हो गया है। पंचायती राज अधिनियम में कार्यकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने के भीतर नए सिरे से चुनाव करवाना बताया गया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायती चुनाव को समय पर करवाने को लेकर 9 जनवरी को एक फैसला पारित किया। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने फैसले में पंचायती चुनाव को 30 अप्रैल तक करवाने को लेकर सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं।

खंडपीठ ने राज्य चुनाव आयोग पंचायती राज विभाग और शहरी विकास विभाग को निर्देश दिया है कि वह आपसी खींचतान खत्म कर चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में मिलकर काम करें। राज्य चुनाव आयोग को एक बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए राज्य सरकार, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के साथ बातचीत करते हुए तालमेल बिठाए ताकि सुचारू रूप से पंचायती चुनाव करवाए जाएं। चुनाव आयोग बड़े भाई की तरह काम करेगा और अन्य सभी संवैधानिक अंगों के साथ मिलजुल कर पंचायती चुनाव को करवाने के लिए बैठक करेगा और निर्णय लेगा। अदालत ने कहा था कि जहां पर पुनर्सीमांकन का कार्य पूरा हो चुका है वहां आरक्षण रोस्टर का काम तुरंत किया जाए, लेकिन जहां पर नहीं, वहां पर 28 फरवरी तक पूरा करने को कहा है।

इंडिया गठबंधन का अलोकतांत्रिक रवैया? बीजेपी का आरोप- पीएम नरेन्द्र मोदी पर हमला कर सकते थे विपक्षी सांसद

नई दिल्ली।

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन को संबोधित करने से कुछ ही मिनट पहले लोकसभा स्थगित कर दी गई। यह घटनाक्रम विपक्षी सांसदों के जोरदार विरोध प्रदर्शन के सत्ता पक्ष के साथ झड़प में तब्दील होने के बाद हुआ, जिससे दोनों पक्षों के बीच तीखे आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दावा किया कि कई विपक्षी महिला सांसद सदन के वेल में घुस गईं, प्रधानमंत्री की कुर्सी की ओर बढ़ीं और वरिष्ठ मंत्रियों की बार-बार की गई अपील को अनसुना कर दिया। तिवारी के अनुसार, स्थिति नियंत्रण से बाहर होने के कारण प्रधानमंत्री सदन में प्रवेश नहीं कर सके। मनोज तिवारी ने कहा कि आज जो कुछ हुआ, उसकी तस्वीरें देखकर आप दंग रह जाएंगे। यह स्थिति दर्शाती है कि चूंकि जनता उन्हें (कांग्रेस को) हरा रही है, इसलिए वे हमें (भाजपा को) संसद में बोलने नहीं देंगे। देश ने इतना बड़ा सम्मान हासिल किया है, फिर भी वे इसे मनाने नहीं देंगे, और वे प्रधानमंत्री मोदी को बोलने से रोकने के लिए ये सब कर रहे हैं। पूरा देश सब कुछ देख रहा है, और देश कांग्रेस से जवाब मांगेगा। तिवारी ने आरोप लगाया कि वे प्रधानमंत्री के बैठने की जगह पर चढ़ गए। उन्होंने खूब हंगामा किया। उन्होंने आगे दावा किया कि विपक्षी सांसद आक्रामक हावभाव के साथ आगे बढ़े और उनके व्यवहार से सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा हुईं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वे प्रधानमंत्री पर हमला भी कर सकते थे। विपक्षी सांसद नारे लगाते हुए सदन के वेल में घुस गए और उनके हाथों में एक बड़ा बैनर था जिस पर लिखा था, जो उचित लगे वो करो। तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सदस्य भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए और जैसे-जैसे विरोध तेज होता गया, उन्होंने हूटिंग शुरू कर दी। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है... राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान इस तरह का हंगामा पहली बार हुआ है। ये लोग बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हैं... ये क्या सोचते हैं? क्या इन्हें लगता है कि यह नेहरू परिवार का साम्राज्य है, या कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है, या सोनिया गांधी का घर है...? भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्र को संबोधित करना चाहते थे, लेकिन भारत-भारत गठबंधन के नेताओं ने उन्हें इससे वंचित कर दिया... इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता... पूरा देश इसे देख रहा है और इसकी निंदा कर रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। भाजपा ने आरोप लगाया कि महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी का घेराव किया और उनके आक्रामक व्यवहार से सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा हुईं।

यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में उतरे ओबीसी-एससी/एसटी छात्र, याद दिलाया रोहित वेमुला -पायल तड़वी सुसाइड केस

छतरपुर। जहां देशभर में उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता का संवर्धन विनियम- 2026 का जमकर विरोध हो रहा है, वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में नए नियमों के समर्थन में बुधवार को एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए इन नियमों को सामाजिक न्याय की दिशा में एक अहम कदम बताया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि यह विनियम उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने और वंचित वर्गों के विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित व समान वातावरण सुनिश्चित करने में सहायक होगा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि प्रस्तावित इक्विटी कमेटियों के गठन से संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को मजबूती मिलेगी। छात्रों ने कहा कि रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि विश्वविद्यालय परिसरों में भेदभाव और उत्पीड़न रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देशों की आवश्यकता है। यूजीसी के नए विनियम इसी जरूरत को पूरा करते हैं। छात्रों ने मांग की कि यूजीसी के इन विनियमों को बिना किसी बदलाव के पूरे देश में लागू किया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि नियमों को वापस लेने या कमजोर करने की कोशिश की गई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रशासन की ओर से छात्रों को आश्वासन दिया गया कि उनका ज्ञापन संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। हालांकि प्रशासन की मौजूदगी में प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

जम्मू-कश्मीर में जैश के 2 आतंकियों का एनकाउंटर

उधमपुर। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में बुधवार को सुरक्षबलों ने जैश-ए-मोहम्मद के दो पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया। दोनों आतंकवादी गुफा में छिपे हुए थे। सेना ने गुफा को ग्रेनेड से विस्फोट कर उड़ा दिया। एनकाउंटर का वीडियो भी सामने आया है। इसके बाद एक आतंकवादी का शव गुफा के बाहर था, जबकि दूसरे आतंकी का शव गुफा के अंदर काफी गहराई में मिला। इस ऑपरेशन में जैश का टॉप कमांडर रुबानी उर्फ अबू माविया भी मारा गया। वो इलाके में कई साल से सक्रिय था। मुठभेड़ मंगलवार को शाम 4 बजे शुरू हुई थी। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के पास से M4 कार्बाइन, एके-47 असॉल्ट राइफल और भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया है। व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि CIF डेल्टा, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का यह जॉइंट ऑपरेशन था। इसके तहत इलाके की घेराबंदी की गई। इसे ऑपरेशन 'किया' नाम दिया गया।

राहुल गांधी ने नरवणे की किताब दिखाई, बोले- पीएम को दूंगा

नई दिल्ली।

आर्मी चीफ एमएम नरवणे की जिस किताब को लेकर संसद में दो दिन से हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी बुधवार को वही किताब लेकर संसद पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर आज पीएम आए तो उन्हें यह किताब दूंगा। राहुल ने किताब का वह पेज खोलकर दिखाया, जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ से कहा था- जो उचित समझो वह करो!। राहुल ने कहा कि सरकार और रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि किताब का अस्तित्व नहीं है। देखिए यह रही किताब। राहुल ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री आज लोकसभा में आने की हिम्मत करेंगे। अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो मैं खुद जाकर उन्हें यह किताब सौंपूंगा, ताकि वे इसे पढ़ सकें और देश को इसके बारे में पता चल सके। लोकसभा में दो दिन से पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की अनपब्लिश्ड बुक पर हंगामा हो रहा है। इसके चलते कई बार सदन स्थगित हो चुका है। राहुल इस किताब के अंश लोकसभा में पढ़ना चाहते हैं। स्पीकर ओम बिरला ने इसकी इजाजत नहीं दी है।

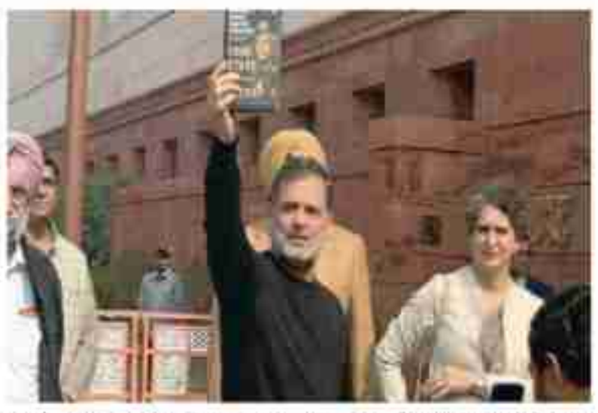

राहुल ने बीजेपी सांसद को कहा- गद्दार दोस्त

इधर, कांग्रेस के कुछ सांसदों ने बजट सत्र के छठे दिन संसद के मकर द्वार के पास प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को पास से गुजरते देखकर कहा कि देखो एक गद्दार आ रहा है, देखिए इसका चेहरा। राहुल गांधी ने हाथ मिलाने की पेशकश करते हुए कहा कि हैलो भाई, मेरे गद्दार दोस्त। चिंता मत करो, आप वापस (कांग्रेस में) आ जाओगे। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि देश के दुश्मनों से मेरा कोई लेना-देना नहीं है।

मणिपुर से सालभर बाद हटा राष्ट्रपति शासन, बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा किया पेश

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की अधिसूचना जारी की। भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित एक घोषणा के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(2) के तहत जारी की गई घोषणा को निरस्त कर दिया है। पिछली घोषणा 13 फरवरी, 2025 को जारी की गई थी। राष्ट्रपति द्वारा बुधवार (4 फरवरी, 2026) को हस्ताक्षरित नई घोषणा में कहा गया है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन वापस ले लिया गया है। घोषणा में लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, द्रौपदी मुर्मू, भारत के राष्ट्रपति, उक्त अनुच्छेद के तहत 13 फरवरी, 2025 को मणिपुर राज्य के संबंध में मेरे द्वारा जारी की गई घोषणा को 4 फरवरी, 2026 से निरस्त करता/करती हूं। यह कदम भाजपा द्वारा मंगलवार को दो बार के विधायक युमनाम खेमचंद सिंह को संघर्षग्रस्त मणिपुर में विधायक दल का नेता घोषित करने और उन्हें राज्य का अगला मुख्यमंत्री नामित करने के एक दिन बाद उठाया गया है। यह निर्णय भाजपा मुख्यालय में पार्टी के विधायकों की बैठक में लिया गया। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। सिंह के दो उपमुख्यमंत्री होंगे, एक कुकी-जो समुदाय से और दूसरा नागा समुदाय से।

कांगपोकपी विधायक नेमचा किपगेन को उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। गठबंधन सहयोगी नागा पीपुल्स फ्रंट द्वारा जल्द ही नागा उपमुख्यमंत्री के नाम की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। 62 वर्षीय खेमचंद सिंह मैतेई समुदाय के सदस्य और एक इंजीनियर हैं। वे पूर्व बीरेन सिंह सरकार में नगर प्रशासन मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। 2022 में, वे मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से एक के रूप में उभरे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले साल 13 फरवरी को मणिपुर के राज्यपाल से संवैधानिक शासन व्यवस्था के टूटने का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। यह निर्णय 9 फरवरी, 2025 को मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के कुछ दिनों बाद लिया गया। उनका इस्तीफा राज्य में लगभग दो वर्षों से व्याप्त जातीय हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के बीच आया था।

नए अवतार में दिखीं सीएम ममता, सुप्रीम कोर्ट में पहली बार किसी सीएम ने की बहस, जजों ने भी ध्यान से सुनी बात

ईसी बंगाल को निशाना बना रहा है - ममता

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शप) प्रमुख एवं पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने बुधवार को कहा कि नयी अमेरिकी शुल्क नीति में भारत में कृषि उत्पादों के निर्यात की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल हैं, जो भारतीय किसानों के लिए चिंता का एक विषय है।

शरद पवार ने बारामती में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत-अमेरिका के हालिया व्यापार समझौते की स्पष्ट तस्वीर अगले दो दिनों में सामने आ जाएगी।

राज्यसभा सदस्य पवार ने कहा, तस्वीर साफ होने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। हालांकि, अमेरिका द्वारा घोषित भारत-अमेरिका शुल्क समझौते में एक प्रावधान है जो भारत में कृषि निर्यात करने की इजाजत देता है, जो भारतीय किसानों और घरेलू कृषि क्षेत्र के लिए चिंता की बात है। उन्होंने कहा, अमेरिका एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है और वहां से बड़े पैमाने पर कृषि निर्यात अन्य देशों के स्थानीय उत्पादकों को नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे उम्मीद है कि भारतीय कृषि क्षेत्र की रक्षा की जाएगी..। इसबीच अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा, राष्ट्रपति (डोनाल्ड ट्रंप) ने भारत के साथ एक और बड़ा व्यापार समझौता किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सीधे बात की। दोनों देशों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। भारत न केवल रूस से तेल खरीदना बंद करने के लिए प्रतिबद्ध है बल्कि अमेरिका से तेल खरीदने के लिए भी प्रतिबद्ध है। संभवतः वेनेजुएला से भी जिससे हमें पता है कि अब अमेरिका और अमेरिकी जनता को सीधा लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में 500 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है जिसमें परिवहन, ऊर्जा एवं कृषि उत्पाद भी शामिल हैं। इसलिए, राष्ट्रपति ट्रंप की बदौलत यह एक और शानदार व्यापार समझौता है।

बीजेपी के लिए महिलाएं केवल वोट बैंक, देश की हालत बिगाड़ी- खरगे

नई दिल्ली। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बुधवार को राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, 6062 शब्दों का अभिभाषण इस सरकार ने तैयार किया है। लेकिन कई अहम सवालों पर अभिभाषण मौन है। मैं सदन में सिर्फ पांच जरूरी मुद्दे आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भाव, संसदीय लोकतंत्र पर हमला, अर्थव्यवस्था और किसानों मजदूरों की दिक्कतें और विदेश नीति की खामियां.. पर अपनी बात रखना चाहता हूं। खरगे ने कहा, आपको यह बताना चाहता हूं कि इस सत्ता ने कितना समय देश की भलाई के लिए दिया है। कितना समय इन्होंने देश के बाहर बिताया। यह आप सबको मालूम है। सबसे पहले मैं सामाजिक न्याय पर बात रखूंगा। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने सामाजिक न्याय के ताने-बाने को कमजोर किया है। उनके संविधानिक हक-हकूकों पर चोट पहुंचाई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में महिला सशक्तिकरण पर बात हुई, लेकिन सच यह है कि महिलाएं भाजपा के लिए केवल वोट बैंक बनकर रह गई हैं। अगर मोदी वाकई महिलाओं का नेतृत्व आगे लाना चाहते हैं, तो सबसे महिला आरक्षण विधेयक पारित करते, इस पर शर्तें नहीं रखते। अगर आपको उन्हें शक्ति देनी है, तो आप ये विधेयक पास कर सकते हैं। उसको लागू कर सकते हैं। आप कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। आप इस पर शर्तें लागू नहीं करते, जैसे आपने जनगणना के नाम पर किया। आपसे सौ साल पहले जब महिलाओं को वोट का अधिकार भी नहीं था। तब कांग्रेस ने अपनी पार्टी की नेता सरोजनी नायडू को अध्यक्ष चुना। है आपके पास कोई उदाहरण? इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के भी साठ साल पूरे हो गए। भाजपा ने किसी महिला को अब तक अध्यक्ष नहीं बनाया है। आरएसएस ने सौ साल में किसी महिला को अपना नेतृत्व नहीं सौंपा है। उन्होंने आगे कहा, कमजोर तबकों, खासकर आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। कांग्रेस की सरकारों में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) समुदाय के आर्थिक विकास के लिए कई कदम उठाए गए। खरगे ने कहा कि सरकार ने मोहम्मद दीपक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, वह सद्भावना के लिए खड़ा हुआ था। एक व्यक्ति जो किसी झगड़े का समाधान करता है, आप उसी को खत्म करते हो, आप देश के लिए कुछ नहीं करते, आप ध्रुवीकरण करते हो। देश में बुलडोजर राजनीति को रणनीति के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हुए खरगे ने कहा कि इनके एक मुख्यमंत्री हैं, वह एक वर्ग के खिलाफ नफरत की राजनीति करते हैं। भाजपा प्रवक्ता बनने की योग्यता यही है कि कौन कितना किसी वर्ग के खिलाफ जहर उगल सकता है। कांग्रेस प्रमुख ने मनरेगा की जगह नए कानून लाने के लिए सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों की हिस्सेदारी चालीस फीसदी कर दी है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य कहां जाएंगे।

सीएम सैनी बोले- दोबारा शिकायत आई तो दिक्कत हो जाएगी, कुरुक्षेत्र में जेई की क्लास लगाई

कुरुक्षेत्र। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा नगर पालिका के जूनियर इंजीनियर को जमकर फटकार लगाई। सीवरेज लीकेज शिकायत पर समाधान न करने पर सीएम ने जेई को कहा कि आज शाम तक करके मुझे बता देना। अगर दोबारा शिकायत आ गई तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। मुख्यमंत्री बुधवार दोपहर को लाडवा के PWD रेस्ट हाउस में जन समस्याएं सुन रहे थे। इसी दौरान एक दुकानदार गंदे पानी की शिकायत लेकर पहुंचा। दुकानदार ने कहा कि नवंबर में गंदे पानी को लेकर शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सीएम की फटकार के बाद नगर पालिका के सेक्रेटरी नीरज सैनी ने कहा कि वहां खुदाई कर पाइप डाले जा रहे थे। इस कारण लीकेज बन रही थी। दुकानदार ने जेई देवेंद्र सिंह को मौखिक रूप में शिकायत दी थी। हम इसे रिपेयर करवा रहे हैं।

सीएम बोले- 6 महीने से चक्कर काट रहा- लाडवा में जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सीवरेज लाइन खाली गई है और उसमें लीकेज हो रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, इसमें कोई किंतु-परंतु नहीं है। अगर लीकेज है, तो इसे बंद कर देना चाहिए था। शिकायतकर्ता पिछले 6 महीने से चक्कर काट रहा है।

अधिकारी ने सीवरेज लीकेज पर सुनवाई नहीं की

जेई बोले- जल्दी करवा देंगे- मुख्यमंत्री ने जेई देवेंद्र सिंह से पूछा, क्या आपको ध्यान में नहीं है कि क्या करना है? इस पर जेई ने जवाब दिया, ध्यान में है जी। फिर मुख्यमंत्री ने कहा, अगर ध्यान में है, तो क्यों तुम इसके चक्कर कटवा रहे हो? जेई ने कहा कि वे जल्दी करवा देंगे। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, इसे आज करवाकर मुझे शाम तक बता देना। यह काम शाम तक हो जाना चाहिए। अगर इसने दोबारा शिकायत कर दी तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी।

मुख्यमंत्री बुधवार दोपहर को लाडवा के PWD रेस्ट हाउस में जन समस्याएं सुन रहे थे। इसी दौरान एक दुकानदार गंदे पानी की शिकायत लेकर पहुंचा। दुकानदार ने कहा कि नवंबर में गंदे पानी को लेकर शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

शिकायतकर्ता गुरमीत ने मुख्यमंत्री को बताया कि वह फौज से रिटायर है और अब वन विभाग में नौकरी कर रहा है। वन विभाग का एक अधिकारी उससे फर्जी बिलों पर साइन करने का दबाव बना रहा है, जब उसने मना किया तो उसे कार्रवाई करने का डर दिखाया। नायब सैनी ने विभाग के अधिकारी पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, कलाल माजरा निवासी सुभाष के सोलर लाइट लगाने की परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के आदेश देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों की रिपोर्ट बनाकर भेजी जाए।

फॉरेस्ट रेंजर मामले में जांच का आश्वासन

तीन महीने पहले पिहोवा के फॉरेस्ट ऑफिस में गार्ड राजू और महिला दरोगा राजबाला ने रेंजर वीरेंद्र सिंह को थप्पड़ मार दिया था। रेंजर की शिकायत पर पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया। साथ ही, विभाग की ओर से दोनों को निलंबित कर दिया गया था। रेंजर की शिकायत के बाद महिला दरोगा ने रेंजर के खिलाफ दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज करवाई। कार्रवाई न होने पर महिला दरोगा ने मुख्यमंत्री से कार्रवाई की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच करवाने का आश्वासन दिया।